आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 27.11.2024 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड ने देहरादून की राज्य औषधि विश्लेषणशाला को औषधि परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया।
- प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण दस दिन के भीतर कर दिए जाएंगे।
- स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू उत्तराखंड के ब्रांड ''हाउस ऑफ हिमालयाज'' ने एक वर्ष से भी कम समय में 34 लाख रुपए से अधिक की बिक्री की।
- कुमाऊं मंडल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2024–25 में आय के आधार पर 843 स्वयं सहायता समूहों का सत्यापन, सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा।

औशधि प्रमाण पत्र जारी

राज्य औषधि विश्लेषणशाला, देहरादून के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गयी है। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड– एन०ए०बी०एल ने देहरादून की लैब को औषधि परीक्षण प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। राज्य के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर० राजेश कुमार ने कहा कि यह प्रमाणपत्र मिलने के बाद इस लैब से जांची गई दवाओं और कास्मेटिक्स को विश्व स्तर पर मान्यता मिल जाएगी। इस प्रयोगशाला में अब तक तीन हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसमें ऑनलाइन प्रमाणीकरण की भी सुविधा है। यह प्रयोगशाला केंद्र सरकार के सहयोग से सात करोड़ रुपये की लागत से बनी है।

स्थानांतरण समयसीमा

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक (एलटी) के अंतर मंडलीय स्थानांतरण दस दिन के भीतर कर दिए जाएंगे। इनमें कुमाऊं मंडल से 223 और गढ़वाल मंडल से 173 शिक्षक शामिल हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। देहरादून में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय बैठक में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति में वरिष्ठता विवाद को दूर करने के लिए शासन स्तर पर चार सदस्यीय समिति कर गठन कर दिया गया है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट विद्यालयी शिक्षा सचिव को सौपेंगी। बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने विभागीय अधिकारियों को अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश भी दिए।

भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को शुभकामनांए देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा, पुलिस के सशक्तिकरण के साथ उन्हें उन्नत तकनीकी के माध्यम से भी जोड़ना है। राज्य सरकार का संकल्प ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। श्री धामी ने कहा कि समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाना है। यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है।

गोश्ठी

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में एक गोष्ठी का अयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्याय प्रक्रिया की आवश्यकताओं, मशीनों, उपकरणों और अन्य संयत्रों की मांग और आकलन पर विचार करना था। गोष्ठी में पुलिस, न्याय विभाग, एफएसएल, सीआईडी, एसटीएफ, साइबर क्राइम, अभियोजन और कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दोरान पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न विभागों को मशीनों, उपकरणों और अन्य संयत्रों की एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इनकी कीमतों का समेकित आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने मशीनों और उपकरणों की कीमतों में समानता के लिए सभी विभागों के लिए एक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

स्वीकृति

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक सौ पन्द्रह करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी है। समिति ने उत्तराखण्ड सहित विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए भी एक हजार एक सौ पन्द्रह करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि में एक सौ 39 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आंवटित हैं। आपदा मद में उत्तराखण्ड के लिए 139 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए स्वीकृत धनराशि से आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान–माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

हाउस ऑफ हिमालयाज

उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए ब्रांड ''हाउस ऑफ हिमालयाज'' ने एक वर्ष से भी कम समय में 34 लाख रुपए से अधिक की बिक्री की है। ग्राम्य विकास विभाग के अधीन, हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र ने पिछले साल दिसंबर में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में किया था। उद्घाटन के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की एकाएक मांग बढ़ी है।

सर्वेक्षण

कुमाऊं मंडल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2024–25 में आय के आधार पर 843 स्वयं सहायता समूहों का सत्यापन, सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा। संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, राजेंद्र तिवारी ने बताया कि समूहों को आय के अनुसार छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके तहत नैनीताल में 280, पिथौरागढ़ में 146, अल्मोड़ा में 247, ऊधम सिंह नगर में 47, चंपावत में 86 और बागेश्वर में 37 समूहों की जांच की जानी है। सर्वेक्षण का कार्य कुमाऊं मंडल के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। श्री तिवारी ने सभी समूहों से अनुरोध किया है कि वे सर्वेक्षणकर्ताओं का सहयोग करें, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

कार्रवाई / अपील

राज्य में मौजूदा भू–कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई जारी है। अपर सचिव, राजस्व, ने बताया कि भू–कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों के इन जमीनों को वापस प्रदेश के लोगों को बेचने की सूचनांए प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने स्थानीय जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा न करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान न हो। अपर सचिव राजस्व ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति ने भू–कानून उल्लंघन कर प्रदेश में जमीन खरीदी है, तो उन प्रकरण में भू–कानून के स्पष्ट प्रावधानों के तहत कार्रवाई की

जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा जमीन राज्य के निवासियों को बेच भी दी जाती है, तो भी उसपर भू–कानून के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी को भी जमीनों की रजिस्ट्री में इस बात पर सतर्कता बरतने को कहा गया है कि भू–कानून के उल्लंघन से जुड़े लोग उन्हीं जमीनों को राज्य के निवासियों को बेचकर नुकसान न पहुंचा पाएं।

स्मार्ट क्लास

हरिद्वार जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जांएगी। जिले की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने आकांक्षी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जिले के 60 आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण कार्य के लिए 27 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इससे इन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आने वाले वास्तविक व्यय का आगणन तैयार किया जा सकेगा

निरीक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देहरादून के धौलास क्षेत्र में निर्माणाधीन 240 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण–एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

और अब एक नजर समाचार पत्र की सुर्खियों पर–

संविधान दिवस की ख़बर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। अमर उजाला राष्ट्रपति के हवाले से लिखता है–हमारा संविधान जीवंत व प्रगतिशील दस्तावेज, अग्रणी अर्थव्यवस्था से लेकर विश्वबंधु की भूमिका तक पहुंचाने में रही अहम भूमिका। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है– संवैधानिक आदर्शों व मौलिक कर्त्तव्यों को आचरण में उतारें। इसी ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है– संविधान सामाजिक न्याय का जरिया।

चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की पुरानी व्यवस्था शुरू करने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने संबंधी समाचार को नवोदय टाइम्स ने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। समाचार पत्र सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है–चुनावों में बैलेट पेपर की वापसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी नवोदय टाइम्स ने लिखा है– जब आप हारते हैं तभी ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, जीतते हैं तो नहीं। राष्ट्रीय सहारा की ख़बर है–बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट की दो दूक, जीतने पर ई.वी.एम खराब नही।

हिंदुस्तान समाचार पत्र ने उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए केंद्र से 139 करोड़ मंजूर करने संबंधी समाचार को प्रथम पेज पर स्थान दिया है।